नईदुनिया

संपादकीय

फिर लोकतंत्र की प्रहरी बनी जनता

अठारहवीं लोकसभा के लिये सात चरणों के चुनाव के बाद आए अप्रत्याशित आकलनों-भविष्यवाणियों से इतर मंगलवार को जो परिणाम सामने आए, उन्होंने पूरे देश को चौंकाया है। पिछले दो बार के आम चुनाव में लगातार भारी बहुमत से सत्ता में आई भाजपा इस बार अपने बूते पूर्ण बहुमत से दूर रह गई। वहीं कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन ने इन चुनावों में उम्मीदों से कहीं ज्यादा सफलता हासिल की। यहां तक कि अब कांग्रेस को लोकसभा में विधिवत विपक्षी नेतृत्व का अधिकार मिलेगा। बहरहाल, वर्ष 2024 के जनादेश ने साफ किया है कि जनता लोकतंत्र में किसी भी दल को स्वच्छंद व्यवहार की अनुमति नहीं देती। वह लोकप्रहरी की भूमिका में आ जाती है। अब चाहे सामने कितना भी कद्दावर नेता क्यों न हो। जनता देश में सशक्त विपक्ष की भूमिका की जरूरत भी महसूस करती है। देश में आपातकाल के बाद भी बदलाव का जनादेश आया था। सही मायनों में यह जनादेश किसी की जीत व हार का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जीत का है। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि सत्तारूढ़ दल निरंकुश व्यवहार करते हुए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षी नेताओं को भयभीत करने को करता है। कुछ विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों को राजनीतिक दुराग्रह के लिये जेल भेजने के आरोप भी लगे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि गठबंधन सरकार के दौर में अब सत्ताधीश निरंकुश व्यवहार नहीं कर पाएंगे। निस्संदेह, इन हालिया चुनाव नतीजों के दूरगामी परिणाम होंगे। इसी साल हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी इन परिणामों का असर दिख सकता है। वहीं, इन चुनाव परिणामों ने समता-ममता के लोकतंत्र की जरूरत को पुष्ट किया है। जनादेश ने भारतीय संवैधानिक संस्थाओं को मजबूती की जरूरत भी बतायी है। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को इस सम्मानजनक स्थिति में लाने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के मुखर प्रतिरोध ने विपक्ष को ताकत दी। वहीं दूसरी ओर इन लोकसभा चुनावों के परिणामों ने सत्ताधीशों को बताया है कि बेरोजगारी, महंगाई और आम जीवन से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हरियाणा व राजस्थान में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया का प्रतिकार युवाओं की अभिव्यक्ति के रूप में इन चुनावों में नजर आने की बात कही जा रही है। पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं को ही नहीं, उनके परिजनों को भी व्यथित किया। युवाओं के देश में हर हाथ को काम देना सरकारों को अपनी प्राथमिकता बनानी होगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटों में गिरावट पार्टी को आत्ममंथन का मौका जरूर देगी। वहीं उड़ीसा व अरुणाचल में भाजपा की अप्रत्याशित कामयाबी भी सामने आई है। अब केरल में उसका खाता खुला है और तेलंगाना में सीटें बढ़ी हैं। उसका वोट प्रतिशत भी कमोबेश बढ़ा है, भले ही ये वोट सीटों में न बदल सके हों। दिल्ली, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल व गुजरात में उसकी बड़ी कामयाबी जरूर पार्टी का उत्साह बढ़ाने वाली है। लेकिन हरियाणा में डबल इंजन की सरकार के बावजूद कांग्रेस की बढ़त पार्टी के लिये चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। भाजपा के एक पक्ष में एक बात यह जरूर है कि देश में वर्ष 1962 में पं. नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के लगातार तीसरे बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड इस बार नरेंद्र मोदी दोहरा सकते हैं। लेकिन ये पार्टी के लिये आत्ममंथन का मौका है कि क्यों पार्टी को अपने बूते सरकार बनाने का अवसर नहीं मिल पाया। यह भी कि अब पार्टी स्वीकारे कि लोकतंत्र सत्तापक्ष और विपक्ष के सामंजस्य व तालमेल से ही समृद्ध होता है। मजबूत विपक्ष लोकतंत्र में सचेतक की भूमिका निभा सकता है। बहरहाल, हाल के वर्षों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने निर्भीक होकर जिस तरह सत्ता पक्ष का मुकाबला किया, देशव्यापी सफल पदयात्राएं की, उससे शेष विपक्ष को मुखर बनाने में मदद मिली। चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस की प्रेसवार्ता में पार्टी ने इंडिया गठबंधन के दलों के साथ मिलकर सत्ता में भागीदारी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। संकेत दिया कि पार्टी के एजेंडे में जाति गणना जैसे मुद्दे प्राथमिकता के आधार पर रहेंगे। निष्कर्ष यह भी कि समाज में आर्थिक असमानता दूर करना इंडिया गठबंधन का मुख्य मुद्दा बना रहेगा।

भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के निहितार्थ

दृष्टिकोण

-डॉ. मयंक चतुर्वेदी

लोकसभा चुनाव-2024 में जिस तरह का चुनावी परिणाम आया है, उसने अच्छे-अच्छे राजनीतिक विश्लेषकों को धूल चटा दी है, एनडीए नीत भाजपा की मोदी सरकार को 300 पार के सभी बड़े-बड़े दावे धरे रह गए और देश की जनता ने मजबूत विपक्ष देकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि सहमति और विरोध का स्वर बराबर का हो, किंतु इसके साथ ही अनेक प्रश्न आज इस बार के चुनावों ने भारतीय राजनीति के लिए समीक्षा करने की दृष्टि से छोड़ दिए है । देश में नया नैरेटिव यह है कि किसी को भी भारत की जनता लोकतंत्र में इतना मजबूत नहीं देखना चाहती कि वह अन्य को छोटा समझने की मानसिकता रखे या उनके बारे में थोड़ा भी कमजोर सोच पाए, लेकिन इसके साथ जो बड़ा प्रश्न आज खड़ा हो गया है, वह है कमजोर सत्ता क्या एक सबल राष्ट्र के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकती है ?

यह आज सभी के सामने है कि कैसे जनता ने भाजपा को पूरी तरह अपने दम सत्ता बनाने से उसे रोक दिया है, किंतु यह सच पूरे भारत का फिर भी नहीं है। देश के कई राज्यों ने शत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। लोकसभा की 542 सीटों की काउंटिंग में दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। देश की राजधानी से ह्रदय प्रदेश मध्य प्रदेश तक भाजपा पर भारत की जनता मोहित है, लेकिन वहीं, एक सच यह भी है कि इस बार का जनादेश बीजेपी से ज्यादा एनडीए के लिए है। बड़ी बात यह है कि दस सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीए का आंकड़ा 300 भी पार नहीं कर पाया और बीजेपी भी बहुमत के 272 के आंकड़े को नहीं छू पाई है, इसलिए उसे अपने सहयोगियों के सहारे देश का शासन चलाना होगा। अब प्रश्न यह है कि क्या ऐसे में देश बड़े निर्णय कर पाएगा?

सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम (सीएमपी) अपनाकर भारत कितना तेजी से आगे विकास करेगा, यह अब देखना होगा। क्योंकि अब तक पिछले दस सालों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भाजपा सरकार सख्त फैसले लेने के लिए स्वतंत्र थी, किंतु इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 10 साल सबसे अधिक परिवर्तनकारी रहे हैं। अब तक भाजपा की मोदी सरकार एक ऐसी सरकार रही है जिसने दशकों पुरानी समस्याओं को हल करने में बड़ी कामयाबी हासिल की । अनुच्छेद 370 को हटाने, सेना के लिए वन रैंक वन पेंशन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, अयोध्या, काशी जैसे धार्मिक क्षेत्र निर्माण, राम मंदिर पुनर्प्रतिष्ठा, मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक क्षेत्र में कई कड़े निर्णय, व्यवसाय के क्षेत्र में जीएसटी, इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, नोटबंदी, काले धन के खिलाफ अभियान, क्रोनी कैपिटलिज्म, सरकारी ठेके में भ्रष्टाचार को खत्म करने विशेष कार्यक्रम, भारतीय उद्योग के लिए आत्मनिर्भर अभियान शुरू करना, नारी शक्ति वंदन कानून, अंतरिक्ष में भारत की ऊंची छलांग के लिए मजबूत कार्यक्रम, खेल सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए निर्णय, सहकारिता आंदोलन को समाज की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय जैसे निर्णय मोदी सरकार के बड़े निर्णय रहे हैं।

इसी तरह से मैन्युफैक्चरर्स के लिए पीएलआई कार्यक्रम ने भारतीय उद्योग को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। आधार कार्यक्रम, डिरेक्ट बेनेफ़िट ट्रांसफ़र (डीबीटी कार्यक्रम) और व्यापक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हों या विदेशी मामलों से जुड़े निर्णय हरेक मोर्चे पर अब तक मोदी सरकार दृढ़ता से खड़ी नजर आई है। पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब करने से लेकर चीन की आक्रामता का वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दिया गया भारत का जवाब, ऐसे अनेक कार्य हैं जिन्हें आज भाजपा की मोदी सरकार को लेकर सफलता के साथ गिनाया जा सकता है और इन्हीं का यह परिणाम भी है कि भारत दुनिया की वर्तमान में तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। किंतु संदेह अब नया है और यह होना स्वभाविक भी है, क्योंकि अब तक तो भाजपा पिछले दो बार से अपने दम सत्ता के लिए आवश्यक नंबर लेकर आ रही थी, वह इस बार अपना स्वयं का बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है। जिसके चलते अब सामूहिक नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (एनडीए) का नया साझा प्रोग्राम देश पर लागू होगा और इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कुल 41 दल शामिल हैं। विषय यह है कि क्या इन सभी के मन की बात को रखते हुए भाजपा मोदी-03 सरकार अपने स्तर पर स्वतंत्र निर्णय ले पाएगी?

भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कई मुख्य बिन्दु हैं, जिन्हें पूरा करने का संकल्प भाजपा का है । जिसमें कि सरकार ने 70 साल की उम्र से ऊपर के किसी भी वर्ग के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज, गरीबों के लिए 3 करोड़ घर, गरीबों को मुफ्त राशन 2029 तक देने की गारंटी तो है ही, साथ में एक राष्ट्र-एक चुनाव और समान नागरिक संहिता के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है।

भाजपा के संकल्प पत्र में अन्य मुख्य बिन्दु देखें तो मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना, सभी घरों में स्वच्छ पेयजल, गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली, अधिकाधिक आईआईटी, आईआईएम, एम्स और अन्य ऐसे संस्थान खोलना, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, पेपर लीक रोकने के लिए कानून , विद्यार्थियों के लिए स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर) एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी को लागू करना, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों में वृद्धि, तीर्थ यात्रा योजना, उच्च शिक्षा संस्थानों में इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना, सब्जी उत्पादन एवं भंडारण के लिए नए क्लस्टर, भारत को उच्च मूल्य सेवा केन्द्र बनाने के लिए, नए वैश्विक पूंजी केन्द्र, वैश्विक प्रौद्योगिकी केन्द्र और वैश्विक इंजीनियरिंग केन्द्र की स्थापना, भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, गगनयान को प्रक्षेपित करना तथा चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री को उतारना, भगवान राम की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने जैसे अनेक संकल्प रखे गए । वस्तुत: भाजपा अपने तीसरे कार्यकाल के जरिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की गारंटी दे रही है। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी भारत करे, इसके लिए तैयारियां होनी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विसेज, स्टार्टअप और टूरिज्म और खेल के जरिये लाखों रोजगार देश में पैदा हों, इस पर काम होना है। नारी तू नारायणी के तहत आगे तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने की भाजपा की योजना है। इसी प्रकार से अन्य कई योजनाओं पर काम करने का संकल्प भाजपा ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए ले रखे हैं, वास्तव में अब देखना यह होगा कि ताजा राजनीतिक हालातों में भाजपा की केंद्र सरकार क्या अपने लिए इन संकल्पों को सहजता के साथ पूरा कर पाएगी?

इस जनमत के निहितार्थ भी समझिए

नजरिया

-विश्वनाथ सचदेव

भाजपा पर संविधान को बदलने की कोशिशों की बात कांग्रेस पार्टी ने उठायी थी। आरोप यह था कि भाजपा संविधान को बदलकर देश को तानाशाही की ओर ले जा सकती है। भाजपा ने इस बात का पुरजोर खंडन किया और हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहेब अंबेडकर की दुहाई देकर संविधान में अपनी आस्था प्रकट की।

आशाओं और आशंकाओं के बीच झूलते हुए लोगों ने आम-चुनाव के परिणामों को देखने-समझने की कोशिश की है। इसी समझ का एक परिणाम यह भी है कि सारा चुनाव-प्रचार इस बात का साक्षी रहा है कि संकल्प-पत्र की गारंटियों और घोषणापत्रों के दावों के बावजूद कम से कम भाजपा की ओर से यह चुनाव मुद्दों से कहीं अधिक पार्टी के 'एकछत्र नेता' के नाम पर अधिक लड़ा गया था। हमारे संविधान में भले ही ऐसी कोई व्यवस्था न हो, पर पिछले चुनाव की तरह ही इस बार भी अमेरिका की राष्ट्रपति-प्रणाली की तरह चुनाव लड़ने की कोशिश सत्तारूढ़ दल ने अवश्य की थी। ऐसा नहीं है कि इस बार मुद्दे थे ही नहीं, पर मुद्दों की जगह जुमले ज़्यादा उछले। 'इंडिया एलायंस' ने ज़रूर संविधान की रक्षा जैसे सवाल उठाये और महंगाई बेरोज़गारी की बात की, लेकिन यह भी हमने देखा कि चुनाव-प्रचार के दौरान संविधान को बदलने की कोशिशों के संकेत भी दिये गये।

भाजपा पर संविधान को बदलने की कोशिशों की बात कांग्रेस पार्टी ने उठायी थी। आरोप यह था कि भाजपा संविधान को बदलकर देश को तानाशाही की ओर ले जा सकती है। भाजपा ने इस बात का पुरजोर खंडन किया और हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहेब अंबेडकर की दुहाई देकर संविधान में अपनी आस्था प्रकट की। यह कहना तो मुश्किल है कि संविधान को लेकर उठे इस मुद्दे का चुनाव के नतीजे पर क्या और कितना असर पड़ा, पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की इस बात ने देश के नागरिकों के एक वर्ग को चौकन्ना अवश्य बना दिया था। संविधान को लेकर इधर चर्चाएं भी हो रही हैं। यही वह समय है जब यह ज़रूरी हो गया है कि देश में संविधान की महत्ता और उसे लेकर उठाये जा रहे सवालों पर देश का प्रबुद्ध नागरिक विचार करे।

हमारे संविधान-निर्माताओं ने इस बात को रेखांकित करना जरूरी समझा था कि यह देश हर भारतीय का है। जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारा संविधान नागरिक के कर्तव्य और अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या करता है। था एक वर्ग जो समान अधिकार के नाम पर 'राजा और गंगू तेली' को समानता देने के तर्क को समझ नहीं पाया था, पर देश की सामूहिक चेतना ने हर नागरिक को वोट का अधिकार देकर यह सुनिश्चित कर दिया था कि जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाला हमारा गणतंत्र क्षमता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के ठोस आधारों पर खड़ा है। यहां हर एक के वोट का अधिकार समान है; यहां हर एक को न्याय पाने का अधिकार है; यहां हर एक को विकास का सामान अधिक अवसर मिलेगा; यहां हर एक को अपनी आस्था के अनुसार जीवन-यापन करने की सुविधा मिलेगी। देश के नागरिक को यदि किसी बात की गारंटी की आवश्यकता है तो वह इस बात की है कि उसे एक सार्वभौम स्वतंत्र देश के गौरवशाली नागरिक के रूप में जीने का अधिकार और अवसर प्राप्त हो। हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है। यही गारंटी इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि देश का हर निर्वाचित शासक संविधान के बुनियादी ढांचे के अनुरूप कार्य करेगा। समय और स्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन अवश्य हो सकता है, पर संविधान की मूल आत्मा को बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। क्या है यह संविधान की मूल आत्मा? इस प्रश्न का उत्तर हमारे संविधान की प्रस्तावना में छिपा है। हमारे संविधान-निर्माताओं ने इस प्रस्तावना में स्पष्ट शब्दों में कहा था, 'हम भारत के लोग एक समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, जनतांत्रिक गणतंत्र' की स्थापना करते हैं। हमने इस संविधान को स्वयं आत्मार्पित किया था। सौ से अधिक बार आवश्यकता के अनुसार संविधान में संशोधन हो चुके हैं, पर प्रस्तावना में वर्णित अवधारणाओं को कहीं छेड़ा नहीं गया। समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, जनतांत्रिक गणतंत्र यह चार शब्द मात्र शब्द नहीं हैं, इन चार शब्दों में वे सारे सपने समाहित हैं जो हमने 75 साल पहले अपने लिए देखे थे। देश का हर प्रयास उन सपनों को पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम होना चाहिए।

जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो इसका अर्थ हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर देना मात्र नहीं है। मनुष्य मात्र की समानता में विश्वास करने वाला सिद्धांत है यह। मैं भी जियूंगा, तुम भी जियो; मेरे पास एक रोटी है, आओ हम आधी- आधी बांटकर कुछ भूख मिटा लें। यही मनुष्यता है। इसी मनुष्यता का तकाज़ा यह भी है कि हम एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हुए स्वतंत्रतापूर्वक विकास की सीढ़ियां चढ़ें। यहां विकास का अर्थ बड़े-बड़े कल-कारखाने अथवा लंबी-चौड़ी सड़कें मात्र नहीं है, मनुष्य का सर्वांगीण विकास इसकी परिभाषा है। हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर व्यक्ति स्वयं को दूसरे से जुड़े होने की सार्थकता को समझ सके, यह है वह स्थिति जो हमारे गणतंत्र को सार्थक बनाती है।

18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनावों में हमारे राजनीतिक दलों ने बहुत से वादे और दावे किये हैं। नई सरकार को एक वादा देश के हर नागरिक के साथ करना होगा—संविधान के बुनियादी ढांचे की रक्षा करने का वादा। कोई नयी बात नहीं है यह। हमारा हर निर्वाचित प्रतिनिधि और निर्वाचित सरकार का हर सदस्य संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। इस रक्षा का सीधा-सा अर्थ यह है कि हम उन बुनियादी मूल्यों-आदर्शों के अनुरूप जीवन जीने का ईमानदार प्रयास करेंगे जो हमारे संविधान को एक पवित्र ग्रंथ बनाते हैं। सिर्फ माथा टेकने से संविधान की रक्षा नहीं होगी। संविधान के अनुरूप आचरण ही यह रक्षा करेगा।

आजकल

निर्वाचन आयोग ने सीखा सबक

मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई, मगर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि आखिर निर्वाचन आयोग ने क्या सोच कर चुनाव को इतना लंबा खींचा और ऐसे मौसम में मतदान की तारीखें रखीं, जब पूरा उत्तर भारत लू में झुलस रहा होता है।

हर वर्ष गर्मी में तापमान कुछ बढ़ा हुआ दर्ज हो रहा है। लू के थपेड़ों से लोगों की जान चली जाती है। पिछले वर्ष एक ही दिन में अकेले बलिया में करीब डेढ़ सौ लोगों की जान चली गई थी। दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ते वैश्विक ताप को लेकर चिंतित हैं। मगर इसे लेकर खुद सरकारें और उनके तंत्र कुछ गंभीर नजर नहीं आते। इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में मतदान के आखिरी चरण में लू लगने और बुखार की वजह से फिलहाल करीब पच्चीस लोगों के जान गंवा देने के आंकड़े आए हैं।

इसके अलावा पिछले चार दिनों में सात राज्यों से करीब साढ़े तीन सौ लोगों के मरने के आंकड़े मिल रहे हैं। दो साल पहले ऐसी ही जानलेवा गर्मी के मौसम और कोरोना संक्रमण के समय उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए गए थे, जिसमें सौ से अधिक सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के चुनाव तैनाती के दौरान बीमार होकर मरने के आंकड़े आए थे। तब उत्तर प्रदेश अध्यापक संघ ने खासा विरोध दर्ज कराया और मुआवजे को लेकर सरकार पर काफी दबाव बनाया था। अब आम चुनाव के दौरान तैनात कर्मचारियों के मरने की खबरें आई हैं।

स्वाभाविक ही तेज गर्मी में तैनात कर्मचारियों के मरने को लेकर निर्वाचन आयोग की आलोचना हो रही है। मरने वाले कर्मचारियों में अधिकतर छोटी श्रेणी के हैं, जिन्हें लगभग पूरे समय धूप में ही खड़े रहना पड़ा होगा। इनके अलावा, उन हजारों सुरक्षाबलों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिन्हें चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े सहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ा। मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई, मगर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि आखिर निर्वाचन आयोग ने क्या सोच कर चुनाव को इतना लंबा खींचा और ऐसे मौसम में मतदान की तारीखें रखीं, जब पूरा उत्तर भारत लू में झुलस रहा होता है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि निर्वाचन आयोग मई और जून के महीनों में चलने वाली गर्म हवाओं से अपरिचित रहा होगा।

प्रकृति को ओढ़ाते हरियाली की शाल

डॉ. सत्यवान सौरभ

शिक्षक का ओहदा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, जब वह छात्रों को प्रकृति के ऐसा जागरूक करे कि पूरा क्षेत्र ही हरियाली की चादर ओढ़ ले तो उसका स्थान अलग ही हो जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम आपको बता रहे हैं हरियाणा के भिवानी जिले के उपमंडल सिवानी के एक शिक्षक के बारे में जिनके पर्यावरण प्रेम ने छात्रों को इनता प्रोत्साहित किया कि क्षेत्र ने हरियाली की चादर ओढ़ ली। उनकी पर्यावरण की शिक्षा का ऐसा असर हुआ कि नगर के हजारों विद्यार्थी आज पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इतना ही नहीं ये अपने शिक्षक कर्तव्य के साथ भी मन से न्याय कर रहे है तभी इनके कठिन विषय इतिहास में स्कूल के बच्चे टॉपर रहे है और शत प्रतिशत परिणाम हासिल करते हैं। इनकी खास बात ये भी है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चों को पढ़ाते है। बिना प्रायोगिक विषयों में इनके छात्रों का शत प्रतिशत परिणाम प्राप्त करना कोई जादू नहीं इनकी अथाह मेहनत और समर्पण का परिणाम है।

सिवानी के राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूल में पदस्थ शिक्षक राजबीर बेनीवाल (इतिहास प्रवक्ता) के पर्यावरण प्रेम ने नगर सहित पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। ये विद्यार्थियों के साथ वृहद स्तर पर पौधरोपण कर रहे हैं। बचपन से ही प्रकृति के प्रति राजबीर जी के बढ़ते तापमान और घट रही हरियाली के प्रति चिंतन को माता जी ने समझा और उन्हे पौधरोपण के लिए प्रेरित किया। फिलहाल मास्टर राजबीर पर्यावरण संरक्षण के लिए नगर पालिका के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जिसका लाभ शहरवासियों को मिल रहा है। ये आज नगरपालिका सिवानी के स्वच्छता ब्रांड एम्बेस्डर है।

राजकीय मॉडल विद्यालय सिवानी में पदस्थापना के बाद इन्हें प्रिंसिपल सुरेश कुमार और सभी अध्यापकों सहित सुबेसिंह और पूनमचंद बड़वा का विशेष सहयोग मिला, विद्यालय परिसर में ही इसकी शुरूआत हुई, परिसर में पौधरोपण के बाद स्कूल के चारों ओर तथा स्कूल के सामने मार्ग के दोनों ओर वृहद स्तर पर पौधा रोपण किया। शहर की विभिन्न सड़कों के साथ-साथ श्री कृष्णा प्रणामी स्कूल, बिश्नोई मंदिर और नगर की श्मशान भूमि जहां हरियाली नहीं थी, जैसे विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण किया।

शिक्षक राजबीर बेनीवाल के पर्यावरण प्रेम ने धीरे-धीरे सभी का ध्यान खींचा। उनके पर्यावरण प्रहरी नामक महाअभियान से अब नगर के सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों सहित प्रकृति प्रेमी जुडने लगे। लोगों के जुड़ाव का ही यह परिणाम है कि नगर से लगभग 7-7 किलोमीटर दूर तक हजारों पौधों का लक्ष्य रखकर वृहद स्तर पर पौधरोपण किया गया। सिवानी का पर्यावरण प्रहरी आज अभियान बन गया है।

मास्टर राजबीर ने नियमित रूप से खुद के खर्च से खुद ही बीज या कलम से पौधे तैयार करके आते-जाते रास्ते में लगाने शुरू कर दिए। साथ-साथ नि:शुल्क लोगों को वितरित भी करते रहे। इसी प्रक्रिया को मास्टर राजबीर ने लगातार जारी रखा। राजबीर जी बताते हैं, शिक्षा विभाग में रहते हुए बार-बार स्थानान्तरण के चलते मुझे कई गांवों में सेवा का मौका मिला। इस दौरान मुझे प्रकृति के कई रूप देखने को मिले और मेरे प्रकृति प्रेम को जुनून में तब्दील होते देर नहीं लगी।

वर्तमान में मास्टर राजबीर खुद तो पेड़-पौधों का संरक्षण कर ही रहे हैं, साथ ही दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी जुनून के चलते आज वह सिवानी उपमंडल में कई जगह पौधे लगा चुके हैं। मास्टर राजबीर को जहां कहीं भी किसी संस्था द्वारा आमंत्रित किया जाता है, वहां पहुंचकर लोगों को विशेष रूप से बच्चों को प्रकृति के संरक्षण का पाठ पढ़ाते हैं। प्रकृति के प्रति अपने काम को ही अपने जीवन का कर्तव्य मानते हैं।

1993 में इन्होंने सिवानी के इसी विद्यालय से 12वीं पास की और तत्पश्चात इतिहास और अंग्रेजी में एमए किया। अतिरिक्त एलएलबी डिग्री से सुशोभित मास्टर राजबीर के पौधे लगाने के जुनून के चलते स्कूल के माध्यम से प्रकृति प्रेम जारी रहा। मकसद और लक्ष्य बड़ा होने लगा तो मास्टर राजबीर ने 2021 में पर्यावरण प्रहरी ट्रस्ट नामक स्वयंसेवी संस्था की शुरुआत की, जिसके बाद लोगों को प्रकृति संरक्षण के बारे में जागरूक करना इनका लक्ष्य हो गया। इसके तहत वर्तमान में वह पर्यावरण के हित में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संस्थान व स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए शिक्षण का कार्य भी कर रहे हैं। जब उनसे लोगों को कोई संदेश देने के बारे में पूछा गया, तो पेशे से शिक्षक मास्टर राजबीर का कहना है, हर माता-पिता को अपने बच्चे को मिट्टी से खेलने देना चाहिए। इसके अलावा, मां-बाप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक स्थानों पर भ्रमण कराने ले जाएं, जिससे बच्चे प्रकृति के करीब जाएंगे। इससे बच्चों में बचपन से ही धरती मां के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होगा।